MA (Sem-II) Pol. Science Dr. S. B. Kumar

MPOLCC-07

# DEVELOPMENT ISSUES

## Bretton Woods System : IMF & WORLD BANK

## ब्रेटन वुड्स व्यवस्था : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक

ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की स्थापना 1944 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में 44 देशों के शासनाध्यक्षों का एक अंत० सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने मुद्रा विनिमय का एक अंत० पैमाना को जन्म दिया अर्थात् अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की मुद्रा का विनिमय। इसके साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) एवं विकास एवं पुनर्संरचना का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-World Bank) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। विकास एवं पुनर्संरचना का अंतर्राष्ट्रीय बैंक ही वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक भी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं के विनिमय दर को डिजाइन (समायोजन) करने ~~के लिए किया गया था जबकि दूसरे विश्व बैंक का निर्माण के पीछे अल्प विकसित राष्ट्रों~~ तथा व्यापार घाटे से जूझ रहे राष्ट्रों को उधार देने के उद्देश्य से किया गया था जबकि विश्व बैंक का उद्देश्य अल्पविकसित राष्ट्रों को विकास के लिए ऋण मुहैया कराना था। हालांकि समय के साथ-साथ दोनों अंत० वित्तीय संस्थाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया है।

ब्रेटन वुड्स व्यवस्था 1971 में खत्म हो गई जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर एवं सोने के आबंध (Link) को गंभीरता से लिया। 1973 तक विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले स्वतंत्र कर दिया। यह एक कठिन संक्रमण था जो अंत० स्तर पर तेल के बढ़ते दाम, बैंक की असफलता तथा मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाता है।

ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंग के रूप में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यूं तो विभिन्न देशों की मुद्रा और वित्तीय व्यवस्थाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है लेकिन इसकी स्थापना के पीछे अमेरिका

Scanned with CamScanner

का अपना निजी स्वार्थ भी था और वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पूरे विश्व में विचारधारात्मक आधार पर जो ध्रुवीकरण चल रहे थे, उसको सीमित करना, विशेषरूप से साम्यवादी विचारधारा के ऊपर पूंजीवाद की वरीयता को स्थापित करना और ऐसा तभी संभव था जबकि कोई अंतर्वित्तीय संस्थान जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व हो, के माध्यम से विकासशील अथवा अल्पविकसित राष्ट्रों को ऋण मुहैया कराकर अपने पक्ष में रखा जाय। अमेरिका बहुत हद तक अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा।

विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में इच्छित राष्ट्रों को पूंजी उपलब्ध करवाता है। बैंक के रूप में अपनी मूल संरचना के अनुसार बाजार से उधार लेने की प्रक्रिया इसका मूल कार्य होने से इस बात की कभी संभावना नहीं थी कि वह संयुक्त राष्ट्र (UNO) की समन्वय करने की भूमिका संबंधी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगा। यदि वह एक या दो औद्योगिक रूप से विकसित देशों के प्रभाव से मुक्त हो भी जाए तब भी इसके लिए गैर-वाणिज्यिक रूप से कार्य करना तथा एक देश एक वोट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की वित्त व्यवस्था को चमकाने का कार्य कर सकना संभव नहीं होगा। ऐसा कम ही देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ (विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) आपस में परामर्श कर सकें। बैंक ने निःसंदेह कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं फिर भी वास्तविकता और अपेक्षाओं में अंतर तो होता ही है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह आशा की गई थी कि वह (विश्व बैंक से अधिक) विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों में समता के आधार पर हस्तक्षेप करेगा। इससे अपेक्षा थी कि कोष देशों की वृहत आर्थिक नीतियों को इस प्रकार निर्धारित करवाएगा कि एक बहुराष्ट्रीय उपकरण (Multinational Agent) के रूप में कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में घोषित आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायक होगा। परंतु आज भी अधिकांश देश यह अनुभव करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका मूल रूप से आदिकालीन प्रकृति की है। धन देने वाले देशों की सरकारें इस बात पर बल देते हैं कि वित्तीय नीतियों की समीक्षा मुद्रा कोष के मंच पर ही की जाए न कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप। मुद्रा कोष की शासकीय व्यवस्था में

Scanned with CamScanner

74 प्रतिशत हिस्सेदारी विकासशील देशों की है फिर भी उनकी मतदान शक्ति केवल 34 प्रतिशत है। यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के अनुकूल नहीं मानी जा सकती।

सौभाग्यवश, विश्व बैंक तथा ~~कोष की~~ मुद्रा कोष की नीतियों में सुधार के लिए यह दबाव डाला जा रहा है कि बचत वाले और घाटे वाले देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह भी आशा व्यक्त की जा रही है कि वृहत आर्थिक रणनीतियों (macro economic strategies) के अभाव में विश्व के लिए जो खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, वे इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि यह मुद्रा कोष और बैंक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को व्यापार के समान अवसर प्राप्त करवा सकें। विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की शक्तिहीनता भी एक कारण है जहाँ आर्थिक रूप से सम्पन्न तथा आर्थिक विपन्नता वाले देशों के बीच आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होते जा रही है।

—x—

## Issues between North and South
## उत्तर और दक्षिण के मध्य मुद्दे

प्रस्तुत शीर्षक में उत्तर से तात्पर्य धनी अथवा विकसित देशों से है और दक्षिण से तात्पर्य निर्धन अथवा विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों से है। विश्व के ज्यादातर धनी अथवा विकसित देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में अवस्थित हैं एवं ज्यादातर गरीब ~~देश~~ अथवा विकासशील एवं अल्प-विकसित देश पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्द्ध में अवस्थित हैं। इसलिए उत्तर एवं दक्षिण से तात्पर्य ~~विकसि~~ क्रमशः धनी एवं गरीब देशों से है। विकास के मुद्दे पर दोनों के बीच गंभीर मुद्दे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करवाने के लिए अनेक प्रक्रियाएँ चल रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का न्यायोचित आधार पर विकास किया जा सके। इन प्रक्रियाओं में प्रमुख हैं – नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New Int. Economic Order - NIEO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दृष्टिकोणों ~~के~~ में परिवर्तन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका में वृद्धि, इत्यादि।

Scanned with CamScanner

विकसित उत्तर के देशों तथा विकासशील गरीब दक्षिण के देशों के अन्य समता पर आधारित भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की स्थापना का मुद्दा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्रमुख प्रश्न है। अंतर स्तर पर आज तक भी आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप न्यायपूर्ण नहीं हो सका है। आज भी इस व्यवस्था में उत्तर के विकसित देशों का वर्चस्व बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए इन धनवान देशों (उत्तर) ने अनेक साधनों का प्रयोग किया। जैसे, विदेशी सहायता, बहुराष्ट्रीय निगम (Multinationals Company), IMF, WB इत्यादि। कहने को तो इन संस्थाओं का उद्देश्य निर्धन देशों की सहायता करना था लेकिन व्यवहार में इनका उपयोग पूर्व उपनिवेशों पर नव-औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत करना था। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आज पहले से भी अधिक पक्षपातपूर्ण तथा शोषण करनेवाली हो गई है। 1970 के दशक के ऊर्जा संकट तथा कुछ अन्य घटनाओं ने निर्धन अथवा दक्षिण के देशों को वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट कर दिया है। अतः निर्धन देशों द्वारा NIEO की मांग की गई लेकिन उत्तर के धनी देश इस मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उनका वर्चस्व समाप्त हो जायेगा।

उत्तर और दक्षिण के बीच जो मुद्दे हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर रखा जा सकता है:

1) विकसित और अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों में बढ़ता अंतर → विकसित देशों की जनता तथा अल्पविकसित देशों की जनता के बीच बड़ी खाई (gap) है। विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 30 प्रतिशत है जबकि वे संसार के 70 प्रतिशत सम्पत्ति पर अपना नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर विकासशील देशों की ~~आबादी~~ 70 प्रतिशत से अधिक आबादी 30 प्रतिशत से भी कम संसाधनों और आय पर जीवन व्यतीत करते हैं। विकसित देशों की प्रतिव्यक्ति आय तीन से छः हजार डॉलर के बीच है जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय 100 डॉलर है। 1970 के बाद से यह खाई और भी चौड़ी होते जा रही है।

2) भूमंडलीय पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि — आज भी विकसित देश कच्चे माल एवं सस्ते श्रम (labour) की आपूर्ति के लिए तथा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विकासशील देशों पर निर्भर हैं तथा विकासशील देश आर्थिक एवं

Scanned with CamScanner

प्रौद्योगिकी (technology) प्राप्त करने के लिए विकसित देशों पर निर्भर हैं। लेकिन इस पारस्परिक निर्भरता का लाभ उठाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ही धनी देश व्यस्त हैं। प्रारंभ में पारस्परिक निर्भरता की अवधारणा ने विकासशील देशों को आशान्वित किया था कि अंत० निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि होगी। लेकिन वे आज स्वयं को नव उपनिवेशवाद (Neo Colonialism) के युग में मात्र गौण भूमिका निभाते पाते हैं।

3.) विकासशील देशों पर विकसित देशों का नव-औपनिवेशिक नियंत्रण → भूमंडलीय पारस्परिक निर्भरता अथवा समान संप्रभु स्तर के बावजूद विकासशील देश आज भी नव-उपनिवेशवाद से पीड़ित हैं। संप्रभुता-संपन्न होने से वे सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र राजनीतिक इकाईयाँ जरूर हैं लेकिन आर्थिक एवं व्यवहारिक स्तर पर वे अभी भी विकसित धनी देशों के ऊपर निर्भर हैं। विकासशील देशों पर विकसित देशों का नव औपनिवेशिक नियंत्रण समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक वास्तविकता है। विदेशी सहायता, सैनिक संधियों, भागीदारी, हस्तक्षेप, बहुराष्ट्रीय निगमों, अंत० आर्थिक संस्थानों तथा संरक्षित व्यापार, इत्यादि उपायों के द्वारा धनी देश गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों पर गहन नियंत्रण बनाए हुए हैं। दोनों श्रेणी के देशों के संबंधों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि धनी अथवा विकसित देश अपना नव-औपनिवेशिक नियंत्रण और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि गरीब अथवा विकासशील देश इससे मुक्ति के।

4.) विकसित देशों द्वारा विश्व की आय और उसके संसाधनों का अत्यधिक शोषण → किसी न किसी बहाने धनी देश निर्धन देशों के हितों के विपरित उनके संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। धनी देशों का कच्चे माल के बाजार पर तथा उत्पादित वस्तुओं और पूंजी संयंत्रों पर एकाधिकार (monopoly) है। विकासशील देशों के कच्चे माल के मूल्यों का निर्धारण भी धनी देश ही करते हैं।

5.) बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका → धनी देश बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था एवं नीतियों पर अपना अंकुश रखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों का स्वामित्व (ownership) विकसित देशों के पूंजीपतियों के हाथों में है। USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और

Scanned with CamScanner

कनाडा - इन सात देशों में लगभग 800 विशाल बहुराष्ट्रीय निगम पंजीकृत हैं। ये निगम संसार के कुल उत्पाद के आधे भाग को नियंत्रित रखते हैं। गरीब देश बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा शोषण से पीड़ित हैं।

6.) विकासशील देशों की नीतियों पर विकसित देशों का नियंत्रण → विकसित देश अपनी श्रेष्ठ आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति के द्वारा विकासशील देशों की नीतियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालते हैं।

7.) ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की विफलता → विकासशील अथवा गरीब देश इस बात को अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ब्रेटन वुड्स में स्थापित आर्थिक / वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पक्षपातपूर्ण एवं हानिकारक है। गैट तथा अंकटाड की विफलता, घाटे के मद में व्यय होने वाली विशाल धन राशि, गरीब देशों का बढ़ता ऋण बोझ यह सब कुछ ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की असफलता को दर्शाते हैं।

8.) विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अपर्याप्तता → गैट (GATT) एवं WTO के नए समझौते की अपर्याप्तता ने धनी और गरीब देशों के संबंधों को और भी बिगाड़ दिया है। विकसित देश 'सामाजिक धारा' (Social clause) के द्वारा गरीब देशों की सीमित निर्यात क्षमता पर ~~भी~~ और भी अंकुश लगाने के प्रयास में हैं जिसका गरीब देशों के द्वारा विरोध हो रहा है।

इस प्रकार ~~उत्तरोत्तर~~ उत्तर और दक्षिण के बीच जो मुद्दे हैं वो अधिकांशतः अमीर देशों के हितों के हिमायती हैं जिसे विकासशील ~~और~~ अथवा गरीब देश हटाने की मांग कर रहे हैं और एक नई अंत० आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग कर रहे हैं ताकि सभी देशों को न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त हो सके। अमीर और गरीब देशों की जनता के बीच की खाई को कम किया जा सके।

—×—

उत्तर-दक्षिण संवाद (North-South Dialogue) → संयुक्त राष्ट्र (UNO) द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा पर अमेरिका की पहल पर दिसम्बर 1975 से जून 1977 तक पेरिस में अंत० आर्थिक सहयोग सम्मेलन हुआ जिसमें 8 विकसित तथा 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी रियायतें देने के बदले में तेल निर्यातक देशों ~~से~~ (OPEC) से तेल की

Scanned with CamScanner

आपूर्ति में कुछ रियायतें मांगी, जिन्हें उन देशों ने मना कर दिया। यह सम्मेलन असफल हो गया। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष राबर्ट मैकनामारा ने अंत० विकास मुद्दों के बारे में स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। इस गैर-सरकारी आयोग ने दिसम्बर 1977 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस आयोग के अध्यक्ष पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे, इसलिए इसे ब्रांट आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने अपनी दो रिपोर्टों में जोर देकर कहा कि विश्व शांति के लिए विकसित तथा विकासशील देशों में 'परस्पर-निर्भरता' आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात अक्टूबर 1981 में कानकुन में 22 देशों की बैठक हुई जिससे अंत० आर्थिक विचार-विमर्श (संवाद) के मार्ग की रुकावटों को दूर किया जा सके किन्तु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया।

[ इसके बाद के development को विद्यार्थी अपने प्रयास से पूरा करें ]

—x—

NIEO के उद्देश्य :—

1.) विकासशील देशों की गरीबी दूर करना (Poverty Alleviation)

2.) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकासशील देशों के हितों के अनुरूप बनाना (Int. Trade in favour of the Developing Countries)

3.) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Technology Transfer)

4.) विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग (Economic cooperation among Developing Countries)

5.) अंत० मौद्रिक संस्थाओं में सुधार (Improvement in Int. Monetary Institutions)

—x—

Scanned with CamScanner